



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2762]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940

No. 2762]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

का.आ. 3537(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 787(अ) के तहत विशेष न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले, जयपुर को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य था;

और जबकि, श्री निर्मल सिंह मेरतवाल, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले) स.1, जयपुर जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 21 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2285(अ) के तहत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 21 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2285 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री श्री बुद्धिप्रकाश छानगानी, विशेष न्यायाधीश (सीबीआई मामले) सं. I, जयपुर को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-II)]

प्रवीण वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2018

**S.O. 3537(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 787 (E) dated the 26<sup>th</sup> April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Special Court, Central Bureau of Investigation Cases, Jaipur, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Rajasthan for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Nirmal Singh Meratwal, Special Judge (CBI Cases) No. 1, Jaipur, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2285 (E) dated the 21<sup>st</sup> July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2285 (E) dated the 21<sup>st</sup> July, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Rajasthan High Court, hereby appoints Shri Buddhiprakash Chhangani, Special Judge (CBI Cases) No. 1, Jaipur, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-II)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.